

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड पर लगाई रोक

यह एडिटरियल 16/02/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Democracy's Guardian Angel" लेख पर आधारित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को नरिस्त कर दिये जाने के बारे में वचिार कथिा गया है। मामले में न्यायालय द्वारा सरकार की दलीलों को खारजि कर दथिा गया और इस बात पर बल दथिा गया कसिंवाधिन इसके संभावति दुरुपयोग की अनदेखी नहीं कर सकता।

प्रलिमिस के लथि:

चुनावी बॉण्ड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951, भारत नरिवाचन आयोग (ECI), वतित अधिनियम 2017, अनुच्छेद 19, 14 और 21

मेन्स के लथि:

चुनाव प्रक्रथिा पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, चुनावी बॉण्ड योजना की परकिलपना और कारथानवयन से उत्पन्न मुद्दे।

सर्वोच्च न्यायालय (SC) की पाँच सदस्यीय संवधिन पीठ ने एक सर्वसमत नरिणय में चुनावी बॉण्ड मामले में हर पहलू पर हर चुनौती को बरकरार रखा और इस योजना को असंवैधानकि घोषति कर दथिा। इसने SBI को चुनावी बॉण्ड जारी करना तुरंत बंद करने और बकिरी कथिा गए बॉण्ड से संबंधति सभी जानकारी और सभी दाताओं एवं प्राप्तकर्त्ताओं के नाम भारत नरिवाचन आयोग (ECI) को सौंपने का आदेश दथिा।

चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme) क्या है?

■ चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds):

- चुनावी बॉण्ड वचन पत्र की तरह के धन साधन हैं, जनिहें भारत में कंपनथिों एवं व्यक्तथिों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से खरीदा जा सकता है और इन्हें कसिी राजनीतिक दल को दान दथिा जा सकता है, जो फरि इन बॉण्डों को भुना सकता है।
 - ये बॉण्ड केवल कसिी पंजीकृत राजनीतिक दल के नरिदषिट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं।
- कोई व्यक्त व्यक्तगित रूप से अकेले या अन्य व्यक्तथिों के साथ संयुक्त रूप से ये बॉण्ड खरीद सकता है।

■ चुनावी बॉण्ड योजना:

- भारत में राजनीतिक फंडगि को भ्रष्टाचार-मुक्त करने के लथि वर्ष 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना शुरू की गई थी।
- चुनावी बॉण्ड योजना के पीछे का मुख्य वचिार भारत में चुनावी वतितपोषण में पारदर्शति लाना था।
- सरकार ने इस योजना को 'कैशलेस-डजिटल अस्थव्यवस्था' की ओर आगे बढ़ रहे देश में एक आवश्यक 'चुनावी सुधार' बताया था।

- केवल नागरकिों के सशक्तीकरण के बारे में नहीं है, अपति यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनप्ररिभाषति करता है।" वविचना कीजथि। (2018)

■ वर्ष 2022 में योजना में कथि गए संशोधन:

○ 15 दनिों की अतरिकित अवधति:

- इसके तहत एक नया पैरा पेश कथिा गया, जसिमें कहा गया कसि राजथिों की वधिनसभा और वधिनमंडल वाले केंद्रशासति प्रदेशों के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा पंद्रह दनिों की अतरिकित अवधति नरिदषिट की जाएगी।
- वर्ष 2018 में जब चुनावी बॉण्ड योजना शुरू की गई थी तो ये बॉण्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में से प्रत्येक में 10 दनिों की अवधति के लथि उपलब्ध कराए गए थे, जैसा किकेंद्र सरकार द्वारा नरिदषिट कथिा जा सकता है।
- लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30 दनिों की अतरिकित अवधति नरिदषिट की जानी थी।

○ वैधता (Validity):

- चुनावी बॉण्ड जारी होने की तथिसे पंद्रह कैलेंडर दनिों के लथि वैध होंगे और यदवैधता अवधति समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा कथिा जाता है तो कसिी भी भुगतान प्राप्तकर्त्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं कथिा जाएगा।

- कसिी अरुहति राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा कयिा गया चुनावी बॉण्ड उसी दनि भुना दयिा जाएगा ।
- पात्रता (Eligibility):
 - केवल वे राजनीतिक दल जो [जन प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 \(RPA, 1951\)](#) की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जनिहोंने पछिले लोकसभा चुनाव में या राज्य वधिनसभा के चुनाव में कम से कम 1% मत हासलि कयि थे, चुनावी बॉण्ड प्रापुत करने के पात्र होंगे ।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को क्यों नरिसुत कर दयिा?

- सूचना के अधिकार का उल्लंघन:
 - न्यायालय ने माना कयिह योजना गुमनाम या गुप्त राजनीतिक दान की अनुमतिदेकर संवधिन के [अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) के तहत सूचना के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है ।
 - न्यायालय ने कहा कयि ऐसा अधिकार केवल वाक् एवं अभवियकृत स्वातंत्र्य की पूरुत करने तक ही सीमति है, बल्क सरकार को जवाबदेह बनाकर सहभागी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है । इस प्रकार, यह केवल साध्य का साधन नहीं है, बल्क सिवयं में एक साध्य है ।
- नरिणय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कयि धन एवं राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण आरुथकि असमानता राजनीतिक संलग्नता के वभिन्न स्तरों का नरिमाण करती है । इसके परिणामस्वरूप, इस बात की वैध संभावना बनती है कयि कसिी राजनीतिक दल को वत्तितय दान देने से 'बदले में कुछ प्रापुत करने' या प्रतदिान व्यवस्था (quid pro quo arrangements) का नरिमाण होगा ।
- काले धन पर अंकुश लगाने में आनुपातिक रूप से उचित नहीं:
 - [के.एस. पुट्टासवामी मामले](#) में अपने वर्ष 2017 के नरिणय में नरिदषिट [आनुपातिकता परीक्षण \(proportionality test\)](#) पर भरोसा करते हुए—जसिने नजिता के अधिकार को बरकरार रखा था, न्यायालय ने रेखांकति कयिा कयि सरकार ने अपने उद्देश्य को प्रापुत करने के लयि न्यूनतम प्रतबिधात्मक तरीका नहीं अपनाया है ।
 - ऐसे न्यूनतम प्रतबिधात्मक तरीकों के उदाहरण के रूप में [मुख्य न्यायाधीश](#) ने गुप्त दान पर 20,000 रुपए की सीमा और चुनावी ट्रस्ट (Electoral Trusts) की अवधारणा का हवाला दयिा जो दानकर्तुताओं से राजनीतिक दान प्रापुत करने की सुवधि प्रदान करता है ।
 - न्यायालय याचिकाकर्तुताओं की इस दलील से भी सहमत हुआ कयि चूँक काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य की पुष्टि [अनुच्छेद 19\(2\)](#) के तहत नरिदषिट कसिी भी युक्तयुक्त नरिबंध से नहीं की जा सकती, इसलयि इसे सूचना के मूल अधिकार को प्रतबिधाति करने का वैध उद्देश्य नहीं माना जा सकता है ।
- दानकर्तुता की गोपनीयता का अधिकार उसके द्वारा दयि गए दान तक वसितारति नहीं है:
 - न्यायालय ने माना कयि राजनीतिक दलों को वत्तितय दान आम तौर पर दो कारणों से दयिा जाता है- समर्थन की अभवियकृत के रूप में और दूसरा, प्रतदिान के उपाय के रूप में ।
 - हालाँक, इसने इस बात पर बल दयिा कयि कॉर्पोरेशन एवं कंपनयिों द्वारा दयि गए भारी राजनीतिक दान को आबादी के कसिी अन्य वर्ग- छात्र, दैनिकि वेतन भोगी कर्मचारी, कलाकार या एक शकिषक द्वारा कयि गए वत्तितय योगदान से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहयि ।
 - इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश ने माना कयि राजनीतिक संबद्धता की गोपनीयता का अधिकार उन योगदानों तक वसितारति नहीं है, जो नीतयिों को प्रभावति करने के लयि कयि जा सकते हैं । इसका वसितार केवल राजनीतिक समर्थन के वास्तवकि रूप में कयि गए योगदान तक ही सीमति है ।
- असीमति कॉर्पोरेट दान स्वतंत्र एवं नषिपकष चुनाव की भावना का उल्लंघन करता है:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कयि [कंपनी अधनियिम, 2013](#) की धारा 182 में कयिा गया संशोधन, जो कंपनयिों द्वारा असीमति राजनीतिक दान की अनुमति देता है, स्पष्ट रूप से मनमाना है ।
 - यह प्रावधान भारतीय कंपनयिों को वशिषिट शरुतों के तहत राजनीतिक दलों को वत्तितय दान देने की अनुमति देता है । हालाँक, वत्ति अधनियिम 2017 के माध्यम से कंपनयिों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने की पूरुव-सीमा (पछिले तीन वत्तितय वर्षों के औसत मुनाफे का 7.5%) को हटाने सहति कई महत्त्वपूर्ण बदलाव पेश कयि गए ।
 - इसके अतरिकित, कंपनयिों के लयि उन राजनीतिक दलों के नामों का खुलासा अपने लाभ एवं हानिखातों (Profit and Loss accounts) में करने की आवश्यकता भी समापुत कर दी गई जनिहें उनहोंने दान दयिा है ।
 - मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कयि धारा 182 व्यक्तयिों द्वारा दयि गए राजनीतिक दान को कंपनयिों द्वारा दयि गए दान के समान मानने में गलती करती है कयि कयि कंपनयिों प्रायः प्रतदिान के इरादे से ये दान करते हैं ।
- RPA 1951 की धारा 29C में कयि गए संशोधन को रदुद कयिा गया:
 - आरंभ में, जन प्रतनिधितिव अधनियिम 1951 की धारा 29C में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के सभी दानों की घोषणा करने और यह नरिदषिट करने की आवश्यकता थी कयि कहीं से प्रापुत हुए (व्यक्तगित व्यक्तयिों की ओर से या कंपनयिों की ओर से) ।
 - लेकनि वत्ति अधनियिम 2017 ने एक अपवाद के नरिमाण के लयि इस प्रावधान में संशोधन कर दयिा, जसिमें ऐसी आवश्यकता चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्रापुत दान पर लागू नहीं होगी ।
 - इस संशोधन को रदुद करते हुए न्यायालय ने कहा कयि 20,000 रुपए से अधिक के दान का खुलासा करने की मूल आवश्यकता ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार को दानकर्तुताओं के गोपनीयता के अधिकार के साथ प्रभावी ढंग से संतुलति कयिा है, वशिष रूप से जबक इस सीमा से नीचे के दान राजनीतिक नरिणयों को प्रभावति करने की बहुत कम संभावना रखते हैं ।
- SC द्वारा की गई अन्य टपिपणयिाँ:
 - SBI को आदेश दयिा गया है कयि वह आगे चुनावी बॉण्ड को जारी करने पर तुरंत रोक लगाए और 12 अपरैल 2019 से राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए ऐसे सभी बॉण्डों का वविरण 6 मार्च 2024 तक ECI को प्रस्तुत करे ।
 - इस तरह के वविरण में प्रत्येक बॉण्ड की खरीद की तथिति, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए बॉण्ड का मूल्य शामिल होना

चाहिये।

- ECI भारतीय स्टेट बैंक द्वारा साझा की गई ऐसी सभी सूचनाओं को 13 मार्च 2024 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करे।
- वे चुनावी बॉण्ड जो अभी पंद्रह दिनों की वैधता अवधि के भीतर हैं, लेकिन अभी तक राजनीतिक दल द्वारा भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें वापस करना होगा, जिसके बाद जारीकर्ता बैंक खरीदार के खाते में राशि वापस कर देगा।



Chronology of events in Electoral bonds case

Electoral bond scheme introduced in the Finance Bill

2017

NGO 'Association for Democratic Reforms', lead petitioner, moves SC challenging the scheme

2017
Sep 14

SC issues notices to Centre and EC on PIL filed by the NGO

2017
Oct 03

The Central government notifies electoral bond scheme.

2018
Jan 2

Electoral bond scheme amended to increase sale days from 70 to 85 in a year where any assembly election may be scheduled

2022
Nov 7

SC bench headed by CJI DY Chandrachud refers pleas against scheme to five-judge Constitution bench

2023
Oct 16

Five-judge Constitution bench headed by CJI D Y Chandrachud commences hearing on pleas against scheme

2023
Oct 31

SC reserves verdict

2023
Nov 2

SC delivers unanimous judgement annulling the scheme, calling it 'unconstitutional'

2024
Feb 15

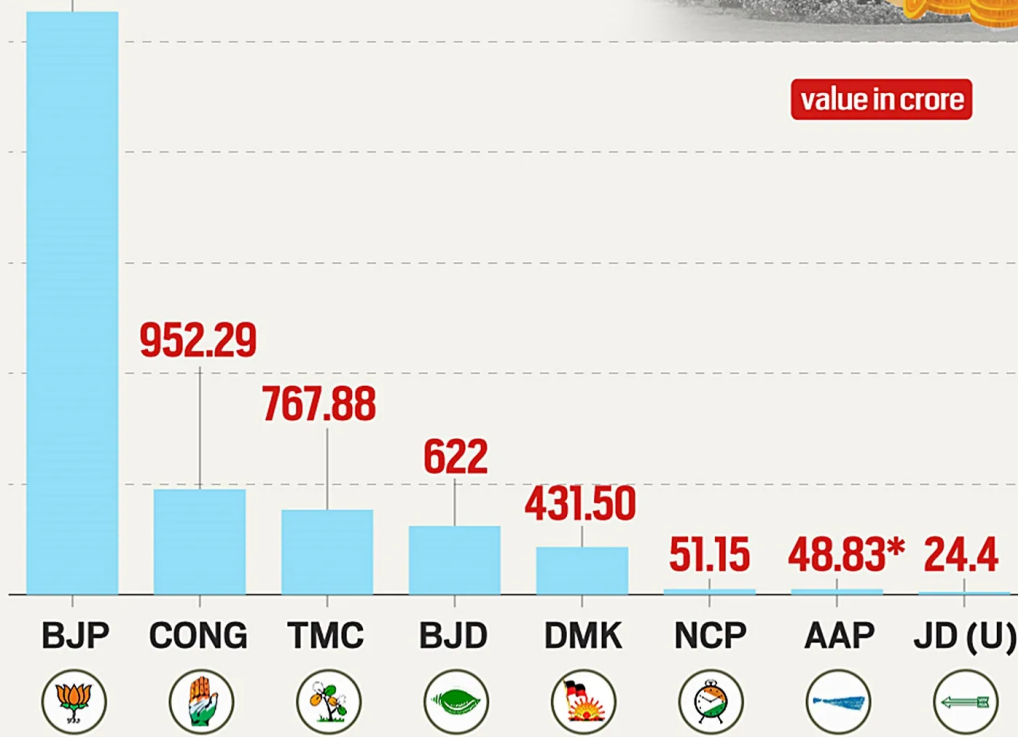
चुनावी बॉण्ड के संबंध में कौन-सी चर्चाएँ व्यक्ति की गईं?

- **इसे लाए जाने के मूल विचार के विरुद्ध:**
 - चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह है कि यह जो करने का उद्देश्य रखती है—यानी चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना, उसके ठीक विपरीत काम करती है।
 - उदाहरण के लिये, आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गुमनामी या अनामकता केवल व्यापक जनता और वपिक्षी दलों के लिये है।
- **जबरन वसूली की संभावना:**
 - चूंकि ऐसे बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, सरकार के लिये यह जानने का अवसर बनता है कि उसके वरिधियों का वित्तपोषण कौन कर रहा है।
 - यह, बदले में, ऐसी संभावना उत्पन्न करता है कि तत्कालीन सरकार धन की जबरन वसूली करे (वर्षीय रूप से बड़ी कंपनियों से) या सत्तारूढ़ दल को धन न देने के लिये उन्हें पीड़ित करे, जहाँ इन दोनों ही रूपों में सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ प्राप्त होता है।
- **लोकतंत्र पर आघात:**
 - **वित्त अधिनियम 2017** में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दे दी है।
 - इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं को यह पता नहीं होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस दल को और कितनी मात्रा में धन दिया है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों के लिये मतदान करते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।
- **जानने के अधिकार (Right to Know) से समझौता:**
 - भारतीय सर्वोच्च न्यायालय लंबे समय से यह मानता रहा है कि 'जानने का अधिकार', विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
- **स्वतंत्र एवं नष्पिक्ष चुनाव के विरुद्ध:**
 - चुनावी बॉण्ड नागरिकों को कोई विवरण प्रदान नहीं करते हैं। हालाँकि, उक्त गुमनामी तत्कालीन सरकार पर लागू नहीं होती है, जो SBI से डेटा की मांग कर दानकर्ता विवरण तक पहुँच सकती है।
 - इसका तात्पर्य यह है कि सत्तारूढ़ सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र एवं नष्पिक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।
- **'क्रोनी कैपिटलिज्म' (Crony Capitalism):**
 - चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक दान पर सभी पूर्व-मौजूदा सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से संसाधन-संपन्न नगिर्मों को चुनावों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है, जिससे आगे 'क्रोनी कैपिटलिज्म' का मार्ग प्रशस्त होता है।
 - क्रोनी कैपिटलिज्म: ऐसी आर्थिक प्रणाली जो कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ एवं पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों से चहिनति होती है।
- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफॉर्मस (ADR) रिपोर्ट 2023 में जताई गई चर्चाएँ:**
 - **दान और धन स्रोतों के विषय अनुपात का विश्लेषण:**
 - चुनावी बॉण्ड के माध्यम से सबसे अधिक दान (कुल 3,438.8237 करोड़ रुपए) वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुआ जो आम चुनाव का वर्ष था।
 - वर्ष 2021-22 (जिसमें 11 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए) में चुनावी बॉण्ड के माध्यम से 2,664.2725 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ।
 - विश्लेषण में शामिल 31 राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल 16,437.635 करोड़ रुपए के दान में से 55.90% चुनावी बॉण्ड से, 28.07% कॉर्पोरेट क्षेत्र से और 16.03% अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ।
 - **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल:**
 - वित्त वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच राष्ट्रीय दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान में 743% की वृद्धि हुई।
 - इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय दलों को प्राप्त कॉर्पोरेट दान में केवल 48% की वृद्धि हुई।
 - क्षेत्रीय दलों को भी चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का बड़ा हिस्सा मिला।
 - **चुनावी बॉण्ड का सत्ता-पक्षपाती दान:**
 - राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में सत्तारूढ़ दल को सबसे अधिक दान प्राप्त हुआ। सत्तारूढ़ दल को प्राप्त कुल दान का 52% से अधिक भाग चुनावी बॉण्ड से प्राप्त हुआ, जिसकी राशि 5,271.9751 करोड़ रुपए थी।
 - प्रमुख वपिक्षी दल 952.2955 करोड़ रुपए के साथ चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान के मामले में दूसरे स्थान पर रहा (उसे प्राप्त कुल दान का 61.54%), जबकि देश की तीसरे सबसे बड़े दल को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से 767.8876 करोड़ रुपए (उसे प्राप्त कुल दान का 93.27%) प्राप्त हुए।

The bond funds

Total value of **electoral bonds** sold from 2017-18 to 2021-22:
Rs 9,208.23 crore

5,271.97



* Electoral bond / electoral trust contribution

भारत में चुनावी वित्तपोषण के संबंध में कुछ प्रमुख सुझाव

■ दान का वनियमन:

- कुछ व्यक्तियों या संगठनों, उदाहरण के लिये वदेशी नागरिकों या कंपनियों के दान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दान की सीमाएँ भी निर्धारित की जा सकती हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो कि किसी दल पर कुछ बड़े दानकर्त्ताओं—चाहे वे व्यक्ति हों, नगिम हों या नागरिक समाज संगठन हों, का अतिशय प्रभाव न हो।
- कुछ देश राजनीति में धन के प्रभाव को वनियमित करने के लिये योगदान सीमा पर भरोसा करते हैं। अमेरिकी संघीय कानून वभिन्न प्रकार के दानदाताओं पर अलग-अलग योगदान सीमाएँ आरोपित करता है। कुछ अन्य देश, जैसे क्यूके, योगदान सीमा तो आरोपित नहीं करते, लेकिन व्यय पर एक सीमा रखते हैं।

■ व्यय की सीमा:

- व्यय पर आरोपित सीमाएँ राजनीति को वित्तीय होड़ से बचाती हैं। वे मतों के लिये प्रतिस्पर्द्धा शुरू करने से पहले ही धन के लिये प्रतिस्पर्द्धा करने के दबाव से राजनीतिक दलों को मुक्त कर देती हैं।
- इसलिये, कुछ देश राजनीतिक दलों पर व्यय सीमा आरोपित करते हैं। उदाहरण के लिये, यूके में राजनीतिक दलों को प्रति सीट 30,000 यूरो (लगभग 30 लाख रुपए) से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम संशोधन (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) की व्यापक व्याख्या से व्यय सीमा आरोपित करने के वधायी प्रयासों को बाधा पहुँची है।

■ राजनीतिक दलों को सार्वजनिक धन उपलब्ध कराना:

- सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वधि है पूरव निर्धारित मानदंड निर्धारित करना। उदाहरण के लिये, जर्मनी में राजनीतिक दलों को राजनीतिक व्यवस्था में उनके महत्त्व के आधार पर सार्वजनिक धन प्रदान किया जाता है।
- आम तौर पर इसे पछिले चुनावों में उन्हें प्राप्त मतों, सदस्यता शुल्क और नज्दी स्रोतों से प्राप्त दान के आधार पर मापा जाता है। जर्मन

- ‘पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेशन’ को दल-संबद्ध पॉलिसी थकि टैक के रूप में अपने कार्य के लिये समर्पित वशिश राज्य नधि प्रापत होती है ।
- सार्वजनिक वित्तपोषण में एक अपेक्षाकृत नवीन प्रयोग ‘डेमोक्रेसी वाउचर्स’ (democracy vouchers) का है, जसिका उपयोग सफिटल (अमेरिका) में स्थानीय चुनावों में कथिा जाता है । सरकार पात्र मतदाताओं को एक नशिचति संख्या में वाउचर्स वतितरति करती है, जनिमें से प्रत्येक एक नशिचति राशिका मूल्य रखता है ।
- मतदाता इन वाउचर्स का उपयोग अपनी पसंद के उम्मीदवार को दान देने के लिये कर सकते हैं । ये वाउचर्स सार्वजनिक रूप से वतितपोषति हैं, लेकनि धन आवंटति करने का नरिण्य व्यक्तगित मतदाता का होता है । सरल शब्दों में कहें तो मतदाता बैलेट के रूप में वोट देने से पहले अपने धन के रूप में ‘वोट’ देते हैं ।

■ प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:

- वनियमन उपाय के रूप में प्रकटीकरण (Disclosure) इस धारणा पर आधारति है कि सूचना आपूरति एवं सार्वजनिक संवीक्षा राजनेताओं के नरिण्यों और मतदाताओं के मतों को प्रभावति कर सकती है । हालाँकि, दलों को दथि गए दान का अनविार्य प्रकटीकरण हमेशा वांछनीय नहीं होता है ।
- कई बार दानकर्त्ता गुमनामी उनकी सुरक्षा के उपयोगी उद्देश्य को पूरा करती है । उदाहरण के लथि, दानकर्त्ताओं को सत्तारूढ दलों द्वारा प्रतशिोध या जबरन वसूली के भय का सामना करना पड सकता है । प्रतशिोध का यह खतरा दानकर्त्ताओं को अपनी पसंद के दलों को धन दान करने से हतोत्साहति कर सकता है ।
- कई देशों को पारदर्शति और गुमनामी की इन दो वैध चतिाओं के बीच उचति संतुलन बनाने में संघर्ष का सामना करना पडा है । इस मुद्दे को भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिण्य में संबोधति कथिा है ।

■ चलि का प्रयोग:

- ‘आरक्षति योगदान’ (reserved contributions) की चलि की प्रणाली के तहत, दानकर्त्ता राजनीतिक दलों को दान हेतु इच्छति धनराशिका को ‘चलि इलेक्टोरल सर्वसि’ को हस्तांतरति कर सकते हैं जो दाता की पहचान का खुलासा कथि बना दल को वह राशिका अग्रेषति कर देता है ।
- यद्यथि पूरी गुमनामी प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करे तो राजनीतिक दल कसिी वशिषिट दाता द्वारा दान की गई राशिका पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे और फरि प्रतदिन व्यवस्था का नरिमाण करना अत्यंत कठनि होगा ।
- हालाँकि, यह दानकर्त्ताओं (जो सरकारी संरक्षण चाहते हैं) और राजनीतिक दलों (जनिहें धन की आवश्यकता है) के हति में होगा कथिे उन दानकर्त्ताओं द्वारा दान की गई राशिका पता लगाने के लथि अनौपचारिक रूप से पहले से ही समन्वय करें । वस्तुतः जैसा कथि वर्ष 2014-15 में हुए वभिनिन घोटालों से खुलासा हुआ, चलि के राजनेताओं और दानकर्त्ताओं ने पूर्ण गुमनामी की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अप्रभावी करने के लथि एक-दूसरे के साथ समन्वय कथिा था ।

■ पारदर्शति और गुमनामी को संतुलति करना:

- सबसे प्रमुख प्रतकिरथिाओं में से एक यह होगा कि पारदर्शति और गुमनामी में वैध सार्वजनिक हतिों को संतुलति कथिा जाए । कई देश छोटे दानकर्त्ताओं को गुमनाम बने रहने की अनुमतति देकर इस संतुलन को कायम रखते हैं, जबकि बड़े दान के खुलासे की आवश्यकता होती है ।
- यूके में, कसिी राजनीतिक दल को एक कैलेंडर वर्ष में एक ही स्रोत से प्रापत कुल 7,500 पाउंड से अधिक के दान की रपिर्ट करने की आवश्यकता होती है । जर्मनी में यह सीमा 10,000 यूरो है ।
- इस दृष्टिकोण के पक्ष में तरक यह है कि छोटे दानकर्त्ताओं की सरकार में सबसे कम प्रभावशाली होने और पक्षपातपूर्ण उत्पीडन के प्रतिका सबसे अधिक संवेदनशील होने की संभावना होती है, जबकि बड़े दानकर्त्ताओं द्वारा राजनीतिक दलों के साथ प्रतदिन व्यवस्था का नरिमाण करने की अधिक संभावना होती है ।

■ राष्ट्रीय नरिवाचन कोष की स्थापना करना:

- एक अन्य विकल्प यह है कि एक राष्ट्रीय नरिवाचन कोष (National Election Fund) की स्थापना की जाए जसिमें सभी दानकर्त्ता दान दे सकें । राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर धन आवंटति कथिा जा सकता है । इससे दानकर्त्ताओं से प्रतशिोध के बारे में तथ्याकथति चतिा समाप्त हो जाएगी ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान एक नए मुद्दे को भी चहिनति कथिा जो था आतंक या हसिक वरिोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों के लथि राजनीतिक दलों द्वारा प्रापत धन के दुरुपयोग की संभावना और उसने केंद्र से पूछा कि धन के अंतिम उपयोग पर उसका कोई नरिंत्रण है ।

राजनीतिक दलों के वतितपोषण पर प्रमुख अनुशंसाएँ

■ चुनाव के राज्य वतितपोषण पर इंदरजीत गुप्ता समति, 1998:

- कम वतित्तीय संसाधनों वाले दलों के लथि नशिपक्ष अवसर के नरिमाण के लथि राज्य द्वारा चुनावों के वतितपोषण का समर्थन कथिा गया ।
- अनुशंसति सीमाएँ:

- राज्य वतित केवल [राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों](#) को आवंटति कथिा जाएगा, स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं ।
- आरंभ में राज्य वतितपोषण को साधन के रूप में प्रदान कथिा जाए जहाँ मान्यता प्रापत राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं ।
- समति ने आर्थिक बाधाओं को स्वीकार कथिा और पूर्ण राज्य वतितपोषण के बजाय आंशिक वतितपोषण की वकालत की ।

■ नरिवाचन आयोग की अनुशंसाएँ:

- नरिवाचन आयोग की वर्ष 2004 की रपिर्ट में राजनीतिक दलों के लथि अपने खातों को वार्षिक रूप से प्रकाशति करने की आवश्यकता पर बल दथिा गया ताकि आम जनता और संबंधति संस्थाओं द्वारा इसकी संवीक्षा की अनुमतति मिलि सके ।
- [नरिंत्रक और महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) द्वारा अनुमोदति फरमों द्वारा ऑडिट कथिे जाने के साथ, परशिुद्धता सुनशिचति करते हुए ऑडिट कथिे गए खातों को सार्वजनिक कथिा जाना चाहथिे ।

■ वधिआयोग, 1999:

- इसने चुनावों के लथि कुल राज्य वतितपोषण को इस शर्त के तहत ‘वांछनीय’ बताया कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन प्रापत करने

से प्रतर्बिधति कथिा जाए ।

- वधिा आयोग की वर्ष 1999 की रपिीरुत में राजनीतकि दल के खारुतों के रखरखाव, ऑडुटि एवं प्रकाशन के लथिे और गैर-अनुपालन के लथिे दंड के साथ जन प्रतर्निधित्व अधनियिम 1951 में संशोधन करने का प्रसुताव कथिा गया (धारा 78A का प्रवेश कराते हुए) ।

नषिकरुष

15 फुरवरी 2024 भारत के लोकतंत्र में एक ऐतहिसकि दनि है कथिेक सर्वोचुच नुयायालय ने चुनावी बॉणुड योजना को नरिसुत करते हुए एक ऐतहिसकि नरिणय दथिा । नुयायालय ने लोकतंत्र को संवधिन की मूल संरचना के रूड में बरकरार रखते हुए, इसके समकष प्रसुतुत हर चुनौती को संबोधति करते हुए, सर्वसममत नरिणय में इस योजना को असंवैधानकि बताया । इस नरिणय के अनुसार सरकार को चुनावी बॉणुड जारी करना तुरंत बंद करना होगा और भारत के नरिवाचन आयोग के समकष सभी प्रासंगकि सूचना का प्रकटीकरण करना होगा । नुयायालय के नरिणय में इस योजना में सूचना के अधिकार के उल्लंघन को उजागर कथिा गया और सरकार के तरुकों को खारुजि कर दथिा गया, जहाँ नुयायालय ने बलपूरवक कहा कसिं वधिन संभावति दुरुपयोग की अनदेखी नहीं कर सकता है ।

अभुयास प्ररुशुन: चुनावी बॉणुड योजना को नरिसुत करने के सर्वोचुच नुयायालय के नरिणय के महतुत्व और भारत में राजनीतकि वतितपोषण में पारदरुशति के लथिे इसके नहितिारुथ के संबंध में चरुचा कीजथिे ।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्ररुशुन

??????:

प्ररुशुन. भारत के संवधिन के कसि अनुचुछेद के अंतर्गत 'नजिता का अधिकार' संरकषति है?

- (a) अनुचुछेद-15
- (b) अनुचुछेद-19
- (c) अनुचुछेद-21
- (d) अनुचुछेद-29

उतुतर: (c)

??????:

प्ररुशुन. "सूचना का अधिकार अधनियिम केवल नागरकिों के सशकुतीकरण के बारे में नहीं है, अपतुति यह आवशुयक रूड से जवाबदेही की संकल्पना को पुनप्ररुभाषति करता है ।" वविचना कीजथिे । (2018)